

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—148/2019/223 (2019/00148)

1. गोकुलसिंह पुत्र खेमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम दुदा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बस्तीराम पुत्र गणेश,
2. कैलाशचन्द्र पुत्र गणेश,
3. किशोर पुत्र गणेश,
4. मांगीलाल पुत्र गणेश,
समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम रामपुरा, दुदा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर
जरिये मुख्त्यारआम मदनलाल पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल, निवासी
कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया दोगम, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. श्रीमती राधा देवी पत्नि हुक्मसिंह,
7. नौरत पुत्र हुक्मसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता राधादेवी पत्नि
हुक्मसिंह,
8. अरविन्द पुत्र हुक्मसिंह, नाबाबलगब जरिये सरंक्षम माता राधादेवी पत्नि
हुक्मसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम दुदा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध
निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 5.2.2019 अंतर्गत
प्रकरण संख्या 104/2018 (153/2011).

उपस्थित:—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील रेस्पो० संख्या 1 से 4
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 5.
4. प्रफोर्मा रेस्पो० संख्या 6 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:— 17.2.2020

1. हस्तगत अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो० संख्या 5 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो० के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत

धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 156, 164, 321 कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 5 बिवंसी ग्राम रामपुरा दूदा, पटवार क्षेत्र धोलादांता, तह0 टॉटगढ़, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके रिकार्डेड सहखातेदार बख्ताराम, शिवजी पिता पन्ना, बस्तीराम, केलशचंद्र किशोर, मांगीलाल पिता गणेश, जाति रेगर निवासी ग्राम रामपुरा—दुदा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर है । उक्त सहखातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा द्वारा वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादीगण को बैचान कर दी है, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है । सहखातेदारान द्वारा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42—बी का स्पष्ट उल्लंघन कर आराजी का बैचान किया गया जजो कानूनन उक्त आराजी धारा 175 के तहत बिलानाम श्री सरकार दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्ट कर वर्तमान अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 7 का वाद स्वीकार किया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 जरिये मुख्तारआम के द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील बख्ताराम बनाम सरकार पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.8.2018 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में पुनः सुनवाई बाबत् प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 5.2.2019 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 5 का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये एवं मान0 न्यायालय के पूर्व निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना तथा मान0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का कोई पृथक से प्रतिवाद पत्र के अभाव एवं बिना कब्जा के अभाव में खातेदारी प्रदान करने का आदेश विधि विरुद्ध प्रदान किया गया जबकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 एवं उनके पूर्वज के द्वारा जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा को बैचान कर, अपीलांट के पिता एवं बाद में अपीलांट काबिज बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजी का विक्रय होने पर धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत विक्रेता के अधिकार समाप्त हो जाते है । धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की कार्यवाही मात्र राज्य सरकार एवं अपीलांटस के मध्य होने के बावजूद मात्र वर्तमान अपीलांटस की आराजी हड़पने के लिए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को लाभान्वित करने की गरज से धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से विवादित आराजियात के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की थी जिसमें अपीलांटस के मौके

- पर काबिज काश्त होने के बावजूद अधी०न्याया० ने मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी०न्याया० ने पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2016 (2) पेज 1147 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.2019 की सूचना प्रार्थीगण को अपने अधिवक्ता से दिनांक 20.4.2019 को मिलने जाने पर हुई । अधिवक्ता ने अवगत कराया कि निर्णय की सूचना डाक द्वारा दी गई किन्तु उक्त सूचना अपीलांटस को प्राप्त नहीं हुई जिससे निर्णय की समय पर जानकारी नही हो सकी थी । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 से 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय विधिसम्मत है । विवादित आराजियात रेस्पो० संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी की आराजियात है जिस पर आज दिवस तक रेस्पो० संख्या 1 से 6 ही काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात बाबत् रेस्पो० अथवा उनके पूर्वजों द्वारा अपीलांटस के पक्ष में किसी प्रकार का बैचान इकरार निष्पादित नही किया गया है एवं न ही उनकी जानकारी में है । उक्त इकरारनामा फर्जी एवं अवैध होकर प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । वैसे भी 100/-रु० से अधिक राशि की अचल सम्पति के बैचान/हस्तांतरण के दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है । तथाकथित इकरारनामा अपंजीकृत एवं अवैध है तथा इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई धारा 175 की कार्यवाही भी कानूनन पोषणीय नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो० ने बहस में यह भी कथन किया कि वादी ने पूर्व में रेस्पो० संख्या 1 से 6 को धारा 175 की कार्यवाही में पक्षकार कायम बिना एकतरफा में दिनांक 26.6.2014 को निर्णय प्राप्त किया था जिसे मान० न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से निरस्त किया गया है । अधी०न्याया० के समक्ष रेस्पो० संख्या 1 से 6 द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया था जिसे अधी०न्याया० ने विधिसम्मत रूप से स्वीकार किया है तथा वादी का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो० ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 (2) आर०आर०टी० पेज 1164 डी०बी०, आर०आर०डी० 2000 डी०बी० पेज 34, 2017 (1) डी०एन०जे० (राज०) पेज 422 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।
7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण के गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी०न्याया० की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तोजात का गहनता से अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य

निर्विवाद है कि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पूर्वजों के नाम से रिकार्ड में रही है । यह तथ्य भी प्रमाणित है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलान्टस जाति से रावत होकर गैर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है के द्वारा अपीलान्टस जो कि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है के पक्ष में विक्रय के इकरारनामे तहरीर किये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत कार्यवाही किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 5 का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये थे । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय दिनांक 26.6.2014 के विरुद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.8.2018 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 26.6.2014 को निरस्त कर निर्देश जारी कर प्रकरण अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । उक्त प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने वाद में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को पक्षकार कायम कर वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया है ।

9. अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी कि“ आया ग्राम रामपुरा दूदा की वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 156, 164, 321 कुल किता 3 कुल रकबा 1-15-05 को जरिये ईकरार बेचान का कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42-बी का स्पष्ट उल्लघन कर स्वयं की खातेदारी भूमियों का स्वेच्छा से गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को विक्रय किया है जिसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 5 पर था जिसके संबंध में वादी द्वारा ईकरारनामा दिनांक 10.7.1997 की छाया प्रति प्रस्तुत की थी । उक्त ईकरारनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पन्ना वल्द दूला उर्फ दल्ला, जाति रेगर द्वारा राशि 60,000/-रु0 में हुकमसिंह व गोकुलसिंह पि0 खीमसिंह, जाति रावत को बेचान का इकरार किया जाना अंकित है । परन्तु जमाबंदी अनुसार पन्ना का उक्त खसरा संख्या 156 में किसी प्रकार का कोई हक निहित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त बेचार इकरारनामे अपंजीकृत है तथा केवल मात्र नोटेरी से तस्दीक किये हुए है । सम्पति अंतरण अधी0 1882 के अनुसार 100/-रु0 से अधिक की सम्पति के बेचान/हस्तांतरण पर दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त बेचान इकरारनामे प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42-बी का उल्लघन किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 का तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. तनकी संख्या:-2- आया अप्रार्थी ने उक्त भूमियों का पूर्ण प्रतिफल अदा कर सद्भाविक रूप से क्रय किया है एवं अप्रार्थी के पक्ष में नियमन किया जाना आवश्यक है एवं उक्त वाद निरस्त योग्य है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 2 पर था । प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने तनकी संख्या 2 को साबित करने के संबंध में इकरारनामा दिनांक 10.7.1997 की छाया प्रतिय पेश की थी जिसके संबंध में तनकी संख्या 1 में विस्तृत रूप से यह विवेचन किया जा

चुका है कि उक्त इकरारनामे में पन्नालाल वल्द दल्ला नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होने से पन्ना वल्द दूला उर्फ दल्ला को बेचान किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसके अतिरिक्त उक्त बेचान इकरारनामे अपंजीकृत है जबकि सम्पति अंतरण अधि० 1882 के अनुसार 100/-रु० से अधिक की सम्पति का दस्तावेज पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है। जिससे उक्त बेचान इकरारनामे अवैध एवं शून्य होने तथा अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जा सकते हैं। जब अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत इकरारनामे अवैध एवं शून्य है तो इसके आधार पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार भी प्राप्त नहीं होते हैं। अधि० न्याया० ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध विधिसम्मत रूप से किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। तनकी संख्या 2 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

11. तनकी संख्या:-3- आया प्रतिवादीगण का आज दिवस तक संयुक्त रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामा अन-रजिस्टर्ड है जो कि प्रतिवादीगण की जानकारी में ही नहीं है एवं प्रतिवादी के खातेदारी हकों एवं अधिकारों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं शून्य है जिसके आधार पर वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 से 6/रेस्पो० संख्या 1 से 4 पर था। रेस्पो० संख्या 3 ने 6 ने अधि० न्याया० के समक्ष अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि तथाकथित बेचान इकरारनामे अपंजीकृत दस्तावेज है तथा विवादित भूमि पर आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 3 से 6/रेस्पो० संख्या 1 से 4 का कब्जा काशत होना अंकित किया है। इस संबंध में तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णय में विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है कि अपीलांटस के पक्ष में तथाकथित इकरारनामे अपंजीकृत होने तथा सम्पति हस्तांतरण अधि० 1882 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे अवैध एवं शून्य इकरारनामे के आधार पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधि० न्याया० ने विधिसम्मत रूप से तनकी संख्या 3 रेस्पो० संख्या 1 से 4/प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पक्ष में निर्णित की है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

12. तनकी संख्या:-4-आया वादग्रस्त आराजी को बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश गलत एवं विधि के विरुद्ध होने से उक्त आधार पर किये किये गये नामांतरण एवं इंद्राज आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को वादग्रस्त आराजी में खातेदार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 पर था। पत्रावली एवं अधि० न्याया० के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो० संख्या 1 से 4 द्वारा अधि० न्याया० के समक्ष विवादित आराजियात को सिवायचक घोषित किये जाने के कारण पुनः स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु काउण्टर क्लेम एवं जवाबदावा प्रस्तुत कर शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा संदर्भ में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 1 से 3 के विस्तृत निर्णय से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस के पक्ष में तथाकथित निष्पादित इकरारनामे अपंजीकृत होकर अवैध एवं शून्य है क्योंकि कानूनन सम्पति अंतरण अधि० 1882 के अनुसार 100/-रु० से अधिक की सम्पति के दस्तावेज का कानूनन पंजीकृत होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बेचान इकरारनामे की छाया प्रतियां होकर अपंजीकृत है दस्तावेजात है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा

100/-रु0 से अधिक की सम्पत्ति के संबंध में होने से सम्पत्ति अंतरण अधि0 1882 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी अवैध एवं शून्य है। उक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 26.6.2014 में उक्त अवैध एवं शून्य इकरारनामे के आधार पर धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये थे जबकि उक्त बैचान इकरारनामे अवैध एवं शून्य होने से हस्तगत प्रकरण में धारा 42-बी राज0काश्त0 अधि0 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विवादित आराजियात का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पक्ष में निर्णित किया है जो विधिसम्मत निर्णय है। अतः तनकी संख्या 4 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखा जाता है।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 से 4 रेस्पो0 संख्या 1 से [4/प्रतिवादीगण](#) संख्या 3 लगायत 6 के पक्ष में साबित होने से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से अधी0न्याया0 ने अपने पूर्व निर्णय की पालना में विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज किये जाने तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामांतरण को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने के कारण विधिसम्मत है।
14. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय अपीलान्टस के विरुद्ध एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित होने से तथा अपीलान्टस के पक्ष में निष्पादित तथाकथित इकरारनामे कानूनी रूप से शून्य होने से अपीलान्टस को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 6 कानूनी रूप से खातेदारी होकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी सिद्ध होते हैं। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई तात्विक अनियमितता एवं त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।
15. अतः अपील अपीलान्टस निरस्त की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.9.2019 को यथावत् रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर